प्रेस विज्ञप्ति

21 मार्च, 2016

हरियाणा के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज निम्नलिखित बयान दिया:–

श्री मनोहर लाल खट्टर सरकार का दूसरा बजट जनविरोधी, निराशाजनक और निरुत्साहित करने वाला है। इसीलिए हरियाणा के किसी आम जनमानस ने सही कहा है, 'विकास का न खाका और कोरा है बहीखाता'। और खड़ी बोली में अगर हरियाणा की कहें, तो –

कथनी करनी का बुरा हाल, हर वर्ग हुआ बदहाल,

अभी तो हुए हैं, दो साल, क्योंकर कटेंगे तीन और साल।।

यह हरियाणा के लोगों की इस निराशाजनक बजट पर सही मायनों में प्रतिक्रिया है। अगर बिंदुवार देखें, तो हरियाणा में हाल में ही जो व्यापक हिंसा हुई, हमारे दुकानदार भाईयों, व्यवसायियों, बहुत सारे व्यवसायिक संगठनों, उनको जानमाल का भारी नुकसान हुआ। शहरों में आज भी दुकानदार भाई और साथी, व्यवसायिक संगठनों के मालिक, अपनी जिंदगी दोबारा ढर्रे पर लौटाने की बेजोड़ मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने सबको सीमित समय में उचित मुआवजा देने का झांसा और वायदा तो किया था, परंतु इस बजट से साफ हो गया है, कि श्री मनोहर लाल खट्टर जी और उनके वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने एक फूटी कौड़ी भी इस बजट में, केवल चार लाईनों के अलावा इसके लिए नहीं रखी। 35000 करोड़ रु. का नुकसान हरियाणा में हुआ, ऐसा एसोचैम की रिपोर्ट कहती है। क्या वित्तमंत्री और मुख्यमंत्री बताएंगे कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानदार भाईयों और व्यापारियों को मुआवजे के लिए कितनी राशि रखी है, क्योंकि बजट दिखाता है, ऐसी एक फूटी कौड़ी भी इस बजट के अंदर नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है किसान को मुआवज़े का। बजट में बड़े जोरशोर से एक साल बाद मात्र 5 या 6 जिलों में जो सफेद मक्खी का मुआवज़ा दिया गया है, उसकी तो चर्चा की। परंतु पांच ऐसे जिले हैं, जिनमें सफेद मक्खी के मुआवज़े का सर्वे के बावजूद एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई, उसका कोई प्रावधान नहीं। हाल के ही मार्च के महीने में तीन बार लगातार बारिश, आंधी और ओलों के चलते किसान की फसल उजड़ गई। लगभग 30 से 40 प्रतिशत का नुकसान गेहूं की फसल में है, पचास प्रतिशत का नुकसान सरसों की फसल में है, यही हाल सब्जियों और दूसरी फसलों का भी है। दुर्भाग्य से इस बजट में एक फूटी कौड़ी भी मुआवजे की राशि के लिए और किसान को राहत के लिए नहीं रखी गई, ये दर्शाता है कि किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया है, श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने। तीसरी और चिंताजनक बात यह है कि सातवें वेतन आयोग की चर्चा तो की गई, पर हरियाणा के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का फायदा कब से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और उसके बजटरी प्रावधान की एक पैसे की चर्चा भी नहीं की गई। क्या श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार यह बताएगी, कि क्या वो हरियाणा के कर्मचारी को

सातवें वेतन आयोग का फायदा नहीं देने वाली और अगर देने वाली है, तो उसके लिए कितनी राशि रखी है, क्योंकि बजट में कोई राशि नजर आती नहीं। चौथी और एक और महत्वपूर्ण बात है, ऐसा लगता है कि श्री मनोहर लाल खट्टर सरकार रिसोर्सेस जुटाने में, आय जुटाने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है और इसी के चलते ये निर्णय भी इस बजट में आया है, जो चौंकाने वाला है, सनसनीखेज है, कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानि जो सरकारी जमीनें हैं, उनको बेचकर अब सरकार मुनाफा कमाने वाली है। जो अपने घर की संपत्ति बेचकर घर चलाएंगे, वो घर कितने दिन तक बच जाएगा। हरियाणा की गाढ़ी कमाई, जो वर्षों से, दशकों से, सालों से जो हरियाणा की जनता की मिल्कियत है, उसे बेचना हरियाणा के लोगों पर एक कुठाराघात है। इसी प्रकार से इस बजट में चर्चा की गई कि सभी स्वास्थ्य सेवाओं का, रोड और ट्रांसपोर्ट की सेवाओं का, पानी और सीवरेज की सेवाओं का, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर का निजीकरण कर दिया जाएगा, अगर सारी चीज ही प्रायवेट हाथों में सौंप देनी है, तो खट्टर सरकार को क्यों निर्वाचित किया गया था। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर, पानी और बिजली की सेवाओं तक, सारी सेवाओं का निजीकरण करने का एक षडयंत्र इस बजट में पेश किया गया है। और नौकरियों की हालत तो साफ उजागर हो गई, खुद खट्टर सरकार ने यह मान लिया कि वो 1000 से ज्यादा रोजगार नहीं दे पाएंगे, इसलिए लोगों को सरकारी नहीं, प्रायवेट नौकरियों के रहमोकरम पर छोड़ दिया है। सरकार ने बजट में माना कि 5 लाख से अधिक नौजवान हर साल बेरोजगारों की पंक्ति में जुड़ते हैं, और यह भी माना कि खट्टर सरकार उन्हें सरकारी नौकरी देने वाली नहीं। आज जब उद्योग पलायन कर रहा है, आज जब एक भी नया उद्योग हरियाणा में आने को तैयार ही नहीं, तो हरियाणा के बेरोजगार नौजवान को रोजी और रोटी कैसे मिलेगी। पहले ही खट्टर सरकार बेरोजगारों को नौवीं और बारहवीं पास बेरोजगारों को, जो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना था, उस वायदे से पहले ही मुकर चुकी है। और एसवाईएल के निर्माण को लेकर बजट में सरकार का ढ़कोसला और भी मजाक है। एक तरफ बीजेपी की सरकार और अकाली दल की सरकार पंजाब में है, दिल्ली में मोदी जी की बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, एसवाईढल नहर जिसका मुआवजा 40 साल पहले दिया गया, जो 95 प्रतिशत कांग्रेस की सरकार में पंजाब में पूरी हो गई, उस एसवाईएल को भरने का काम पंजाब ने किया, एक गैरकानूनी कानून लेकर आया, चुनाव की राजनीति के चलते, और सुप्रीम कोर्ट तक के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, विधानसभा में पंजाब की, प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, और यहां खट्टर साहब आंख मूंदे बजट में एसवाईएल के निर्माण की बातें करते हैं। सच यह बात है कि हरियाणा के हकों पर एक बार फिर वज्रापात हुआ है, कुठाराघात हुआ है और हरियाणा के हकों को मारा जा रहा है, संघीय ढ़ांचे का दुरुपयोग किया जा रहा है, संघीय ढ़ांचे को तोड़ा जा रहा है, और खट्टर सरकार चैन की नींद बैठी है। ये बजट कोरा एक झूठ का पुलिंदा है, निराशाजनक है, लोकविरोधी है, और इस बजट में मात्र आंकड़ों के खेल के अलावा जनता के लिए कुछ नहीं। इस जनविरोधी बजट को लोग नकारते हैं।